

साप्ताहिक/WE**EKL** 

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 34] नई दिल्ली, बनिवार, अगस्त 21—अगस्त 27, 2004 (आवम 30, 1926) No. 34] NEW DELIH, SATURDAY, AUGUST 21—AUGUST 27, 2004 (SRAVANA 30, 1926)

इस माग में मिन्न पुष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह खलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

वृष्ठ

715

849

1201

होते हैं)

नात [--खण्ड-1--(रझा मंत्रात्य को छोड़ हर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतन न्यायालगद्वारा बारो की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेगों तथा संकल्पों से संबंधित अधिमूचनाएं

भाग 1-खण्ड 2--(रक्षा मंत्रा तय को छोड़ कर) मारन सरकार के मंत्रानयों और उंच्यतन न्यायालय द्वारा नारो की गई सरकारो अधिकारियों को नियुष्तियों, पदोन्नतियों, खुट्टियों आदि के संबंध में अधिनुवनाएं

माग । खण्ड 3 रक्षा मंत्रा वय द्वारा नाशे किए नए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिपूत वाएं माग । खण्ड 4 रक्षा मंत्रा वय द्वारा नारी को गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों बादि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं

े भाग II— खण्ड र् — अविनियम, अध्यादेश और विनियम

साग शास्त्रकार । कार्न्यधिति । मों, अध्यादेशों और विनियमों का द्विन्दी भाषा में अधिकृत पाठ ''

भाग II—खण्ड 2—विधेन तथा विधेनकां पर प्रवर समितियों के बिन तथा रिपोर्ट :

भाग II—खण्ड 3— उप-खण्ड (i)—भारा सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रातयको छोड़ कर) और केन्द्राय शिक-करणों (संघ शासि। क्षेत्रां के प्रगाननां को छोड़ कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियन (जितन गामान्य श्वक्य के आदेश और उपविधियों शादि भो शामि । हैं)

भाग !!-- खण्ड 3-- उपखण्ड (ii) -- भारा नरतार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) और केन्द्रांग प्राक्तिक रणों (संच मासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़ कर) द्वारा बारी किये गये मांतिकित आदेग और अधिनूचनाएं

म्हेंग II--वण्ड 3 उनक्षण्ड--(iii)--गरा नरका प्रके मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भा शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संत्र शासित सेतों के प्रगण्सकों को छोड़कर) द्वारव कारो किये गये सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेणों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल है) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के सामान्य के साम्ब 3 या साम्ब 4 में प्रकाशित

भाग ।]--खण्ड 4--रक्षा मैत्रालय द्वारा जारी किये गये सांविधिक नियम और आदेश

भाग 111-खण्ड 1--उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परिस्तक, संघ सोंक सेंका आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार ते संख्यद्व और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा नारों को गई अधिपुचनाएं ""

भाग III— खन्द 2-- पेटेंट कार्योजय द्वारः जारी की गई पेटेटो और डिजाइनों से सम्बन्धित अखिसूचनाए और नोटिय

माग ।।।—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अञ्चित्तवाएं ं

भाग 111-- खण्ड 4--विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारो को गई अधियूचनाए आदेग, विजापन और नोटिन शामिज हैं \*\*\*

भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकार्यों द्वारा जारी किए ग**र विभायन वर्षर** नोटिस

241

भाग V—अग्रेजी और हिन्दी दोनों म जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शने वासा सम्पुरक

<sup>\*</sup>संकडे भाष्त नहीं हुए ।

.

1-17ť 103

# CONTENTS

Page	Page
FART I.—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statu- tory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 715  PART I.—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 849	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of Geaeral Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence: and by the Central Authorities (other than Administration of Union Territories)
PART I Section 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence
of Defence 3  *** I - Section 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence 1201	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroiler and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Sub-
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	ordinate Offices of the Government of India. 785
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language of Acts, Ordinance and Regula- tions	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and
PART II—Section 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	Designs 6297
** II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statu- tory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministries of the	PART III—Section 3—Notifications issued by or under the Authority of Chief Commissioners—
Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications in- cluding Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies 3759
Part II—Section 3—Sub-Section (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Advertisements and Private Bodies 241
of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territo-	PART V—Supplement showing Statistics of Births and

P mos not recers

1.52

17

# HIT !- SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) मारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय दारा जारी की विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued | by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

# कोयला और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 जुलाई 2004

### संकल्प

सं० 1/3/98-खान-VI (वोत्यूम-III)—भारत सरकार ने अपने दिनांक 24-4-98 के संकल्प संख्या 1/1/95-खान-VI द्वारा ग्रेन इंड उद्योग के विकास के निरीक्षण के लिए एक ग्रेनाइट विकास परिषद का पुनर्गंडन किया गया था जिसका कार्यकाल दो वर्ष की अवधि यानी 31-3-2000 तक था और जिसे बाद में 31-3-2004 तक बढ़ा दिया गया। भारत सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि ग्रेन इंड विकास परिषद का कार्यकाल 31-3-2009 तक बढ़ाना ग्रेनाइट उद्योग के विकास और ग्रेनाइट के निर्यात के हित में होगा और इसके विचारार्थ विषय वहीं होंगे जिनका दिनांक 24-4-98 के संकल्प सं० 1/1/95-खान VI में उल्लेख किया गया है और ग्रेनाइट विकास परिषद का विस्तार कर दिया है तद्नसार इसका संघटन निम्नवत है:—

### अध्यक्ष

- सचिब,
   खान विभाग,
   भारत सरकार, नई दिल्ली।
   सदस्य
- संयुक्त सचिव,
   ब जिज्य मंत्रालय,
   भारत सरकार, नई दिल्ली।
- संयुक्त तिचव,
   पर्यावरण और वन मतालय,
   भारत सरकार, नई दिल्ली।
- संयुक्त सिचन,
   वित्त मंत्रालय,
   राजस्व विभाग,
   मार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
- 5. संयुक्त सचिव, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, आई० पी० पी० विभाग उद्योग भवन, नई दिल्ली।

- 6. सचिव, उद्योग और वाणिज्य विभाग, आंद्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद
- सचिव,
   खान विभाग,
   राजस्थान सरकार, जयपुर
- सचित्र,
   उद्योग विभाग,
   तीमलनाडु सरकार, चेन्नै ।
- प्रधान सचिव, इस्पात और खान विभाग, उड़ीसा सरकार, भुवनेश्वर ।
- सचिव,
   वर्तणज्य और उद्योग विमान,
   कर्नाटक सरकार, बंगलौर।
- सचित्र,
   उद्योग और खान विमान,
   गुजरात सरकार, गांधी नगर।
- क्षायुक्त एवं सचिव,
   उद्योग विभाग,
   केरल सरकार, ति एवन्नतपुरम ।
- महानिदेशक,
   भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेकण
   कोलकाता ।
- महानियंत्रक,
   भारतीय खान भ्यूरो,
   नागपुर।
- 15. निदेशक,
  नेशनल इंस्टीटगुट ऑफ रॉक मैकेनिक्स,
  पी० ओ० चेम्पियन रीक्स,
  कोलार गोल्ड फील्ड्स-563117
  कर्नाटक।
- 16. अध्यक्ष, आल इण्डिया ग्रेनाइट और स्टोन एसोसिएसन, बंगलीर ।

.00

23

TT

Store SVI

> CON Consider

'ive el Section

O la

i daliy Tang D

Stude The T

od cest is as v

नि देव भी

. .

- 17. महासचिव, फेडेरेशन ऑफ इण्डियन मिनरल इण्डस्ट्रीज, नई दिल्ली।
- केपेनिसल,
   वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर,
   14/1-बी एजरा स्ट्रीद,
   दितीय तल, कीलकाता।
- 19. प्रबंध निदेशक,
  ग्रेनाइट (इण्डिया) लिमिटेड,
  143, एल्डम्स रोड, चेन्न-600 018
- 20. मैसर्स पेसिफिक इण्डस्ट्रीज खिनिटेड, बेडला गांव, पी० ओ० बॉक्स 119, उदयपुर-313 001
- 21. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आन्ध्र प्रदेश खनिज विकास निगम, हैटराबाद।
- 22. संयुक्त सचिव, (खनिज नीति तथा विद्यान), खान विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली ।

# और आकलन करना तया इस खनिज के तीता विकास के लिए उपायों की सिफारिश करना। (ii) खानों में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन और

साब विभाग,

23. विदेशक,

इस खानिज के मरेशोगिकी उत्कयन और वैज्ञानिक दोहन के जिए जगायों की सिफारिश करना।

ग्रेनाइट विकास परिषद के जिचारार्थ विषय निम्ब हों है ?

(i) बेनाइट खानों की स्थिति का खावजिक समीका

सदस्य सचिव

(बनिज नीति तथा विधान),

भारत सरकार, नई दिल्ली।

- (iii) ग्रेनाइट के वर्तमान कराधान और रायल्टी ढांचे का मूल्यांकन और ग्रेनाइट में निवेश को और अधिक आकर्षित करने के उपायों का सुझाना।
- (iv) अंति इट और इसके उत्पादों में मूल्य आवर्धन की बढ़ाने के उपायों की सिफारिश करना।
- (v) अन्य कोई पहलू जिसे परिषद देश में ग्रेनाइद्र के खनन और उद्योग के विकास के लिए महूत्य-पूर्ण माने।

प्रशांत मेहता, संयुक्त सांच्य

# MINISTRY OF COAL AND MINES

(DEPARTMENT OF MINES)
New Dethi, the 30th July 2004

## RESOLUTION

No. 1/3/98-MVI. (vol-iii).—A Granite Development Council for overseeing the development of the Granite Industry was reconstituted by the Government of India vide its Resolution of No. 1/1/95-MVI. dated 24-4-98. The tenure of which was for a period of two years i.e. upto 31-3-2000 which was subsequently extended upto 31-3-2004. The Government of India has come to the view that it will be in the interest of development of granite industry and export of granite to extend the tenure of Granite Development Council upto 31-3-2009 with the same terms of Reference as mentioned in Resolution No. 1/1/95-MVI. dated 24-4-98 and the composition of the Granite Development Council has been expanded and accordingly its composition is as under:

### Chairman

Secretary
 Deptt. of Misses,
 Govt. of India, New Delhi.

### Members

- Joint Secretary
   Ministry of Commerce,
   Govt. of India, New Delhi.
- 3. Joint Secretary
  Ministry of Environment & Forests,
  Govt. of India, New Delhi.
- Joint Secretary
   Ministry of Finance,
   Deptt. of Revenue,
   North Block, New Delhi.
- Joint Secretary
   Ministry of Commerce & Industry,
   Deptt. of IPP, Udyog Bhavan,
   New Delhi.
- Secretary
   Industries & Commerce Deptt.
   Govt. of Andhra Pradesh,
   Hyderabad.
- 7. Secretary
  Mines Deptt.
  Govt. of Rajasthan,
  Jaipur.

- 8. Secretary
  Industries Deptt.,
  Govt. of Tamil Nadu,
  Chennai.
- Principal Secretary,
   Steel & Mines Deptt.,
   Govt. of Orissa,
   Bhubaneswar.
- Secretary
   Commerce & Industries Deptt.,
   Govt. of Karnataka,
   Bangalore.
- Secretary
   Industries & Mines Deptt.
   Govt. of Gujarat,
   Gandhinagar.
- Commissioner & Secretary
   Industries Deptt.
   Govt. of Kerala,
   Thiruvanathapuram.
- 13. Director General,
  Geological Survey of India
  Calcutta.
- Controller General,
   Indian Bureau of Mines,
   Nagour.
- Director,National Institute of Rock Mechanics,P.O. Champion Reefs,Kolar Gold Fields-563117,Karnataka.
- 16. PresidentAll India Granite and Stone Association,Bangalore.
- Secretary General, Federation of Indian Mineral Industries, New Delhi.

- 18. CAPEXIL
  World Trade Centre,
  14/1B EZRA Street,
  2nd Floor, Kolkata,
- 19. The Managing Director,
  Granite (India) Ltd.,
  143 Eldams Road, Chennai-600018
- M/s. Pacific Industries Ltd., Bedla Village, P.O. Box-119, Udaipur-313001.
- Chairman-cum-Managing Director Andhra Pradesh Mineral Dev. Corp. Hyderabad.
- Joint Secretary
   (Mineral Policy & Legislation)
   Deptt. of Mines,
   Goyt. of India, New Delhi.

Member-Secretary

- Director,
   (Mineral Policy & Legislation),
   Deptt. of Mines,
   Govt. of India, New Delhi.
- 3. The Terms of Reference of the Granite Development Council will be as follows:
  - (i) To assess and review periodically the status of granite mines and recommend measures for speedy development of the mineral.
  - (ii) To assess technology employed in the mines and recommend measures for npgradation of technology and scientific exploitation of the mineral.
  - (iii) To assess present taxation and royalty structure on granite and suggest measures to make investment in granite more attractive.
  - (iv) To recommend measures for increasing value addition in granite and its products.
  - (v) Any other aspect which the Council deems important in the interest of development of granite mining and industry in the country.

PRASHANT MEHTA. Jt. Secy.